© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 08 | October – December 2017

वश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्थाः एक अध्ययन

Pradeep Kumar
Student (M.Com.)
Govt. P.G. College, Jind

Sachin
Assistant Professor,
G.D. College, Gurugram

सारांशः–

वैश्वीकरण विश्व में चारों और अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण है। वैश्वीकरण शब्द 1980 के दशक से आम बोलचाल की भाषा में आया है। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। वैश्वीकण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण ही भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में आई। वैश्वीकरण से भारत में विदेशी निवेश, आयात-निर्यात, खाद्यान्न, दूरंसचार का विकास, उद्योग, तकनीकी स्थानान्तरण आदि में वृद्धि हुई है।

मुख्य शब्दः– वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश, आयात, निर्यात, भारत

परिचयः– बीसवी शताब्दी के अंतिम चरण की घटना भूमंडलीकरण को सशक्त बनाने और विस्तार करने के दृष्टिकोण से अतिमहत्वूपर्ण रही, जिसकी पृष्ठभूमि 1980 के आर्थिक संकट से तैयार हो रह थी। दो-ध्रुवीय व्यवस्था में एक ओर सोवियत संघ और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्य था। सोवियत संघ के विघटन ने एक टुटे हुए बांध की भूमिका निभाई, जिसके बाद भूमंडलीकरण बाढ के पानी की तरह सभो जगह पहुँच गया। सोवियत संघ जैसे बांध को तोड़ने का श्रेय 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री को दिया गया, जिन्होंने ग्लास्नोस्ट (खुलापन) और पेरिस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की खोज की गई और उसे मजबूत बनाने क लिए उसके नेतृत्व में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जी.ए.ए.टी. (General Agreements on Trade and Tariffs) के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (World Trade organisation) को स्थापित किया गया। आर्थिक क्षत्रों में इन सब प्रयासों का उद्देश्य जिस नीति को लाना था, वह एल.पी.जी. अर्थात् उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatization) और भूमंडलोकरण (वैश्वीकरण) (Globalization) के स्वरूप में थी।[1]

भारत की नयी आर्थिक नीति की घोषणा वर्ष 1991 में की गई। इस नीति में नए आर्थिक सुधारों, जिसमें मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण शामिल हैं, को अपनाया गया है। इन आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बहुत तीव्र करना तथा इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाना था। इस नीति में सरकार ने उत्पादों व सेवाओं के आयात व निर्यात पर लगे टैरिफ व गैर-टैरिफ के प्रतिबंधों को कम कर दिया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशक के लिए खोल दिया